बैंकों की लेखा-परीक्षा

3382 **श्री आस मोहम्मद :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा-परीक्षा चार वर्ष में एक बार होने के कारण बैंकों में भ्रष्टाचार हो रहा है ;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा लेखा-परीक्षा चार वर्ष की बजाय दो वर्ष में करवाए जाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बताया है कि बैंकों में भ्रष्टाचार के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा की आवश्किता की उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि समवर्ती लेखा-परीक्षा एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) 1 करोड़ रुपए की आग्रेम रशि वाली शाखाओं की लेखा-परीक्षा अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष कराई जाती है । शेष शाखाओं में से चौथाई शाखाओं की लेखा-परीक्षा भी प्रतिवर्ष की जाती है । फलस्वरूप कुल शाखाओं के 63 प्रतिशत शाखाओं की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है । परन्तु यदि सभी शाखाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से दो वर्षों में एक बार की जाती है तो इससेन केवल लागत में वृद्धि होगी बल्कि बैंकों के अन्तिम लेखाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में भी विलम्ब होगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण नीति

3383. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऋण-नीति के क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों तथा ऋण लेने वाले व्यक्तियों के बीच अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्वा सरकार नई ऋण-नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रभावशाली बाजार निगरानी प्रक्रिया आरम्भ करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बताया है कि वर्ष 1995-96 के उत्तरार्ध के लिए दिनांक 17 अप्रैल 1995 को घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति का उद्देश्य समग्र चल-निधि में मुद्रा स्फीति दर एवं प्रसार को सीमित करना है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि मौद्रिक एवं ऋण नीति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें परिवर्तन किए जाते हैं । निगरानी की मौजूदा प्रणाली को उपयुक्त समझा जाता है ।

Irregularities in Nationalised banks in Gujarat

3384. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether complaints regarding irregularities committed in the Nationalised banks in Gujarat have been received;

(b) if so, the details thereof during the last three years, and